**भारत सरकार**

**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं० 12**

**दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियां

**12. डा॰ विकास महात्मेः**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में आर्सेनिक से प्रभावित दो हजार और फ्लोराइड से प्रभावित बारह हजार बस्तियां हैं जहां पानी की गुणवत्ता खराब है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी बस्तियां तमिलनाडु में हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य के उन जिलों में पानी की गुणवत्ता की समस्या का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**

**(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)**

(क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 1/4/2017 की स्थिति के अनुसार ,देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 13,492 फ्लोराइड प्रभावित बसावटें और 18,259 आर्सेनिक प्रभावित बसावटें हैं, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना शेष है।

(ख) तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1/4/2017 की स्थिति तक वहां कोई भी आर्सेनिक अथवा फ्लोराइड प्रभावित बसावटें नहीं हैं।

(ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में समर्थन देता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य उन्हें उपलब्ध कराई गई निधियों का 67 प्रतिशत तक जल गुणवत्ता के कवरेज और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फोकस्ड दृष्टिकोण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 22 मार्च 2017 को आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन की शुरुआत की है। इस उप मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र द्वारा आर्सेनिक प्रभावित आबादी और फ्लोराइड प्रभावित आबादी को फोकस्ड वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा जबकि मार्ग में आने वाली गैर-आर्सेनिक और गैर-फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की लागत को, संबंधित राज्य सरकारें, केंद्र अंशदान के समतुल्य राज्य अंशदान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वहन करेंगी। फरवरी-मार्च 2017 के दौरान, उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित राज्यों को चालू नल जल आपूर्ति स्कीमों को पूरा करने के लिए 814.13 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ताकि उनमें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।